दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

1828. **श्री राम नरेश यादव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी भूमि अवैध कब्जे में है और इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) समयपुर बादली में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी, क्या उनको दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वैकल्पिक प्लाट दे दिए है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ये प्लाट कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की लगभग 6500 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है जिसमें 4718 एकड़ ऐसी भूमि शामिल है जिस पर जो यमुना नदी के किनारे किसान सहकारी समिति के अनधिकृत दखल में हैं तथा जिसे न्यायालय से स्थगनादेश के कारण हटाया नहीं जा सका । शेष भूमि पूरी दिल्ली में छितरी हुई है तथा उस पर भारी अतिक्रमण है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इनमें से अधिकांश को हटाने के लिये बेदखली कार्यक्रम का संबंध समय-समय पर पर्याप्त विकसित प्लाटों की उपलब्धता से है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 102 व्यक्तियों को पहले ही वैकल्पिक प्लाट आवंटित कर दिये हैं तथा 125 व्यक्तियों को दिसम्बर, 1988 में वैकल्पिक प्लाटों की पेशकश की गई है । 547 व्यक्ति अभी भी आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जैसे प्लाट उपलब्ध होंगे वैसे ही इन व्यक्तियों को भी उनकी वरिष्ठता के अनुसार प्लाट आवंटित कर दिये जायेंगे ।

Technology from West Germany for rapid transport system in Delhi

1829. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DE VELOPMENT be pleased to state:

(a) whether West Germany has offered latest technology for rapid transit system in the urban areas and if so, the details thereof; and

(b) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Policy for edible oils and pulses to cut down import

1830. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate an edible oil and pulses policy to cut down import; and

(b) if so, the salient features therof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARI KRISHNA SHASTRI): (a) On the recommendations of the Technology Mission on Oilseeds, the

Government has approved an Integrated Policy on oilseeds production, import, distribution and pricing to acclerate self-reliance in edible oil.

There is no proposal under the consideration of the Government for a Pulses Mission. In order to increase production of pulses, a "Pulses Production Development Programme" is being implemented in the country.

(b) The salient features of the Integrated Policy on oilseeds are as under:

— Support to farmers with technology, inputs, credit, etc. to increase oilseed production;

— Raising of PDS prices, in a phased manner to equal the cost of the domestically produced oil, based on support prices;

— Prescription of a price band for wholesale price of edible oils;

— Buffer stocking operation by National Dairy Development Board, (NDDB) with domestically produced and imported stock on maintain prices within the prescribed price band; and

— Creation of a high level Empowered Committee to supervise implementation of the Integrated Policy.

दुधारु पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए निधियां

1831. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों को दुधारु पशुओं की नस्ल सुधारने तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में कितनी धनराशि का आबंटन किया जाता है, इनमें से प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान सहायता के रूप में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और क्या इसके परिणामस्वरूप दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार हुआ है और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए अनुदान सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की है तथा क्या यह आरोप सही है कि पंचायत स्तर पर पशु क्रय समिति द्वारा एक ही पशु को एक ही स्थान पर कई बार क्रय कर लिया जाता है; और

(ग) क्या यह संभव नहीं है कि ग्रामीणों को नकद अनुदान राशि प्रदान करने की बजाय अच्छी नस्ल के पशु प्रदान किए जांए?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) पशुओं की नस्ल में सुधार लाने और दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध विवरण I में दी गई है (नीचे देखिये)।

देश में दूध का उत्पादन 1985-86 के 43.98 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1987-88 में 45.88 मिलियन मीटरी टन हो गया है। गत तीन वर्षों के दौरान दूध का राज्यवार उत्पादन विवरण-II में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पशुओं की नस्ल में सुधान लाने के लिए सहायता